

छोटे शहरों पर देना होगा ध्यान, आरटी-पीसीआर टेस्ट को 70 फीसद करने की जरूरत : पीएम मोदी

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों संग बैठक की। हालांकि बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल शामिल नहीं हुए हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बातचीत करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमें हर हाल में कोरोना महामारी को हराना होगा और इसके लिए मास्क को लेकर गंभीरता अभी भी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश में वैक्सिनेशन की गति लगातार बढ़ रही है। हम एक दिन में 30 लाख लोगों को वैक्सिनेट करने के आंकड़े को भी पार कर चुके हैं, लेकिन इसके साथ ही हमें वैक्सिनेशन की बचाव की समस्या को बहुत गंभीरता से लेना होगा। कोरोना की लड़ाई में वैक्सिनेशन प्रभावी हथियार है। प्रधानमंत्रियों को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को एक साल से ज्यादा हो रहा है। भारत के लोगों ने कोरोना का जिस प्रकार सामना हो रहा है, उसे लोग उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आज देश में 96 प्रतिशत से



ज्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं। मृत्यु दर में भी भारत सबसे कम दर वाले देशों में है। कुछ राज्यों में केंद्रों की संख्या बढ़ रही है। देश के 70 जिलों में ये वृद्धि 150 प्रतिशत से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि हमें कोरोना की इस उभरती हुई दूसरी लहर को तुरंत रोकना होगा। इसके लिए हमें त्वरित और निर्णायक कदम उठाने होंगे। प्रधानमंत्रियों ने कहा कि कोरोना की लड़ाई में हम आज जहां तक पहुंचे हैं, उससे आया आत्मविश्वास, लापरवाही में नहीं बदलना चाहिए। हमें जनता को पैनिंग मोड में भी नहीं लाना है और परेशानी से मुक्ति भी दिलानी है। टेस्ट, ट्रेक और ट्रीट को लेकर

भी हमें उतनी ही गंभीरता की जरूरत है जैसे कि हम पिछले एक साल से करते आ रहे हैं। हर संक्रमित व्यक्ति के कॉन्टैक्ट को कम से कम समय में ट्रेक करना और आरटी-पीसीआर टेस्ट रेट 70 प्रतिशत से ऊपर रखना बहुत अहम है। बता दें कि देश के कुछ राज्यों में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु में बढ़ते संक्रमण ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। इसके मद्देनजर महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के कई शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमण को देखते हुए पुणे,

पिछले तीन वर्षों में आतंकी घटनाओं व घुसपैठ में कमी आई - गृह मंत्रालय

नई दिल्ली (एजेंसी)। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। राज्यसभा में गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि पिछले 3 सालों के दौरान, जम्मू-कश्मीर में सीमा पर से आतंकी घटनाओं और घुसपैठ की कोशिशों में उल्लेखनीय कमी आई है। हालांकि, पिछले 3 वर्षों के दौरान सीमा पर से गोलाबारी की घटनाएं बढ़ी हैं। इससे पहले गृह मंत्रालय ने राज्यसभा में लिखित जवाब में पिछले दो वर्षों के दौरान पड़ोसी देशों से घुसपैठ की संख्या की जानकारी दी। इस दौरान भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर 61, भारत-बांग्लादेश बॉर्डर पर 1045, भारत-नेपाल बॉर्डर से घुसपैठ की 63 घटनाएं सामने आई हैं। वहीं भूटान, म्यांमार और चीन से घुसपैठ की कोई घटना सामने नहीं आई है। मंत्रालय ने बताया कि भारत-बांग्लादेश सीमा पर फेरिंग लागने का काम कठिन भू-भाग, नदी और दलदल भूमि, भूमि अधिग्रहण की समस्याओं, सार्वजनिक विरोध और बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश द्वारा आपत्तियों आदि के कारण पुरा नहीं हो सका। सरकार नियमित रूप से फेरिंग के काम की प्रगति की निगरानी कर रही है। बीएसएफ ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर नदी की सीमा को रखवली के लिए फ्लोटिंग बॉर्डर आउट पोस्ट और नावों के साथ कर्मियों को तैनात किया है। शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को राज्यसभा को बताया कि कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए किसी भी प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक इमारतों को ध्वस्त नहीं किया जाएगा। परियोजना के पहले चरण में 2022 तक नई संसद तैयार हो जाएगी। गृह मंत्रालय के अनुसार जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा 1990 में स्थापित राहत कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार, 44,167 कश्मीरी प्रवासी परिवार पंजीकृत हैं, जिन्हें सुरक्षा चिंताओं के कारण 1990 के बाद से घाटी से जाना पड़ा।

नागपुर और औरंगाबाद ने नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। गुजरात सरकार ने भी अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में

नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। वहीं, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भोपाल और इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू लागू किया है।

एंटीलिया मामला : वाजे ने पहचान छिपाने के लिए पहना था कुर्ता-पजामा, सीसीटीवी में लग रहा था पीपीई किट

मुंबई (एजेंसी)। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर जिलेटिन की छड़ों से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच के निर्यात अधिकारी सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद से हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मुकेश अंबानी के घर के बाहर स्कॉर्पियो पार्क करने वाले पीपीई किट पहने शख्स की तस्वीर पर अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) ने कहा है कि वह शख्स निर्यात पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ही थे। वाजे ने अपनी पहचान छिपाने के लिए पीपीई किट नहीं बल्कि बड़े साइज का कुर्ता पायजामा पहना था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) ने बुधवार को बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज में पीपीई किट पहने नजर आया शख्स सचिन वाजे ही थे। वाजे ने अपनी पहचान छिपाने के लिए ढीलाढाला कुर्ता पायजामा पहना था और सिर पर रमाल बांधा था, जो पीपीई किट

पहनने जैसा नजर आ रहा था। एनआई ने बताया कि एजेंसी ने मंगलवार को वाजे के कार्यालय से एक लैपटॉप जब्त किया था।



लेकिन खास बात यह है कि इसमें से सारा डाटा डिलीट कर दिया गया है। वाजे से उनका मोबाइल मांग गया था, इस पर वाजे ने कहा कि उनका मोबाइल कहीं खो गया है। जबकि जांच में पता चला कि वाजे ने मोबाइल जानबूझकर फेंका था।

वाजे का करीबी चला रहा था इनावा- इससे पहले, एनआई

के सूत्रों ने बताया था कि वह सचिन वाजे ही थे, जो इनावा के चलाकर कर के स्कॉर्पियो के पीछे-पीछे उद्योगपति मुकेश अंबानी के

आवास एंटीलिया के पास तक ले गए थे। इनावा के सहायक ड्राइवर ने एनआई को बताया कि 24 फरवरी को उसकी ड्यूटी खत्म होने के बाद उसने इनावा को पुलिस हेडऑफिस के अंदर खड़ा किया और घर चला गया। यह अभी भी स्पष्ट नहीं है कि वहां से कार को लेकर कौन गया था।

कोरोना का कहर : पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड करीब 29 हजार नए मामले

नई दिल्ली (एजेंसी)। पिछले एक साल से देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है। देश में कोरोना महामारी ने एक बार फिर इस साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इस साल बुधवार सुबह बीते 24 घंटे में पहली बार रिकॉर्ड करीब 29 हजार कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए। केंद्रीय मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस से संक्रमण के 28,903 नए मामले दर्ज किए गए हैं। इसी के साथ देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 1,14,38,734 पहुंच गए हैं। बता दें कि इससे पहले, कोरोना संक्रमण के 28 हजार से अधिक मामले पिछले साल दर्ज किए गए थे। इस साल पहली बार आज कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में इस जानलेवा संक्रमण से 188 लोगों की जान चली गई है,

इसी के साथ मरने वालों की संख्या 1,59,044 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में 17,741 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए हैं। इसी के साथ देश में अब तक 1,10,45,284 मरीज कोरोना वायरस को मात देने में सफल रहे हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केंसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में बेहद कमी दर्ज की गई है। वहीं पिछले तीन महीने बाद कोरोना के सक्रिय मामले एक बार फिर दो लाख के पार पहुंच गए हैं, जबकि इससे पहले सक्रिय मामले दो लाख से नीचे बने हुए थे। फिलहाल, देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 2,34,406 हैं। बता दें कि देश में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड टीकाकरण अभियान का दूसरा चरण जारी है। अब तक 3,50,64,536 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है।

भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान हुआ हादसे का शिकार, एक ग्रुप कैप्टन ने गंवाई जान

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान मिग-21 बाइसन हादसे का शिकार हो गया है। आज सुबह सेंट्रल इंडिया में एक एयरबेस पर कॉम्बैट ट्रेनिंग मिशन के दौरान टेक ऑफ करते वक्त भारतीय वायुसेना का मिग-21 विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में एक ग्रुप कैप्टन की जान चली गई है। हालांकि, इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस बात की जानकारी भारतीय वायुसेना ने दी है। भारतीय वायुसेना ने टवीट कर इस हादसे पर दुःख जताया है। भारतीय वायुसेना ने कहा, इस दुःखद दुर्घटना में इंडियन एयरफोर्स ने अपने ग्रुप कैप्टन ए. गुप्ता को खो दिया। भारतीय वायुसेना गहरी संवेदना व्यक्त करता है और दुःख की इस घड़ी में परिवार के सदस्यों के साथ मजबूती से खड़ा है। दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का



आदेश दिया गया है। बता दें कि इससे पहले जनवरी महीने में 5 तारीख को भारतीय वायु सेना का लड़ाकू विमान मिग-21 राजस्थान के सूरतगढ़ में हादसे का शिकार हो गया था। मिग-21 फाइटर जेट में तकनीकी खराबी के बाद सूरतगढ़ के पास में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हालांकि, हादसे में

पायलट सुरक्षित था। दरअसल, भारतीय वायुसेना ने 1961 में मिकोयान-गुरिचिच डिजाइन ब्यूरो निर्मित मिग-21 विमान को हासिल किया था। इसमें एक इंजन और एक सीट है। यह विभिन्न भूमिका निभाने वाला लड़ाकू विमान है, जो जमीन पर मार करने में सक्षम है।

आईसीयू में भर्ती महिला से नर्सिंगकर्मी ने किया रेप, पति को लिखकर बताई आपबीती

नई दिल्ली (एजेंसी)। राजस्थान की राजधानी जयपुर में दिन को दहला देने वाली घटना सामने आई है। जहां के एक प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू में भर्ती महिला मरीज के नर्सिंगकर्मी द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। नर्सिंगकर्मी ने इस घटना को उस समय अंजाम दिया जब ऑपरेशन के बाद महिला मरीज के मुंह पर ऑक्सीजन लगा हुआ था और दोनों हाथ बंधे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसीयू में पहुंचने के बाद नर्सिंगकर्मी ने पहले मरीज को बार-बार पिंच करके देखा कि महिला होश में है या नहीं, और फिर अश्लीलता करने लगी। नर्सिंगकर्मी की इस हरकत को वजह से महिला मरीज रातभर रोती रही। सुबह होने पर जब महीला ने रात की घटना के बारे में अस्पताल के नर्स को बताने चाही तो आरोपी ने धमकाकर चुप करा दिया।

पति के अस्पताल पहुंचने के बाद खुली पोल- इसके बाद जब महिला मरीज का पति अस्पताल

पहुंचा तो उसने पूरा घटनाक्रम लिखकर अपने पति को बताई। तब जाकर मामला सामने आया। घटना को लेकर महिला के पति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उसके पत्नी की सोमवार को तबीयत खराब होने के बाद वो शहर के शैल्वी हॉस्पिटल लेकर गए थे। जहां डॉक्टरों ने शाम तक महिला का ऑपरेशन करने की बात कही। रात में ऑक्सीजन लगा हुआ था और दोनों हाथ बंधे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आईसीयू में पहुंचने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि वो अंदर नहीं जा सकते हैं। इसके बाद वह घर चले गए। रात में महिला का ऑपरेशन हो गया। जब सुबह वो फिर से अस्पताल आए तो महिला ने अपने साथ हुई ज़्यादाती के बारे में लिखकर बताया क्योंकि ऑक्सीजन लगे होने के कारण वो बोल नहीं सकती थी। घटना की जांच कर रहे डीसीपी ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने ड्यूटी चार्ट व सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान कर ली है और मामले की जांच भी शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन, बढ़ रही पाबंदियां, स्कूल और पार्क बंद

नई दिल्ली (एजेंसी)। देश में कोरोना वायरस के मामले पिछले साल की तरह एक बार फिर तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में कोरोना के नए मामलों ने सरकारों की टेंशन बढ़ा दी है। गुजरात सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू को 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश ने भी पड़ोसी राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भोपाल और इंदौर शहर में नाइट कर्फ्यू लागू किया है। वहीं, महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने पुणे, औरंगाबाद, नागपुर में पहले ही पाबंदियां लागू कर दी हैं। महाराष्ट्र और पंजाब के बाद गुजरात में भी बढ़ते मामलों के कारण स्कूलों में एक बार फिर ताला लगाना शुरू हो गया है।

गुजरात में 31 मार्च तक

नाइट कर्फ्यू- कोरोना के मामलों में उछाल को देखते हुए गुजरात सरकार ने मंगलवार को चार महानगरों- अहमदाबाद, वडोदरा,



सूरत और राजकोट में नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला किया। राज्य सरकार द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि इन चारों शहरों में 17 मार्च से 31 मार्च तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच कर्फ्यू रहेगा। हालांकि गुजरात के इन

शहरों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू लगा हुआ था, लेकिन इसका समय रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक था। इसके अलावा अहमदाबाद के

सभी उद्यानों और पार्कों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। इस दौरान कांकरिया झील और चिड़ियाघर भी बंद रहेंगे।

मध्य प्रदेश में होली पर नहीं होगा सामूहिक कार्यक्रम- कोरोना

संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने कई अहम फैसले किए हैं। भोपाल और इंदौर शहर में रात दस बजे से सुबह छह बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। जबलपुर और ग्वालियर शहर में रात दस बजे से सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन जिलों में होली उत्सव के दौरान कहीं कोई सामूहिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने सोमवार को निर्देश जारी कर वहां से आने वाले लोगों को सात दिन तक क्वारंटाइन करने के निर्देश दिए थे।

राजद्रोह मामलों में केंद्र की कोई भूमिका नहीं, राज्य दर्ज कराते हैं मुकदमे : केंद्र

नयी दिल्ली। राजद्रोह के मामलों में दोषिसिद्धि की दर काफी कम होने को लेकर विपक्ष के निशाने पर आया सरकार ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि ऐसे मामलों में केंद्र की कोई भूमिका



नहीं होती और राज्य सरकारें मामले दर्ज कराती हैं। गुजरात मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कई मामलों में आरोपत्र दाखिल किया गया है वहीं कुछ मामलों में अदालत का फैसला नहीं आ गया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में आरोपत्र दाखिल किया गया है वहीं कुछ मामलों में अदालत का फैसला नहीं आ गया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में आरोपत्र दाखिल किया गया है वहीं कुछ मामलों में अदालत का फैसला नहीं आ गया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में आरोपत्र दाखिल किया गया है वहीं कुछ मामलों में अदालत का फैसला नहीं आ गया है।

दौरान कई विपक्षी सदस्यों ने कहा कि 2019 में 96 ऐसे मामले दर्ज किए गए जिनमें दो मामलों में ही दोषिसिद्धि हुयी। विपक्ष ने सवाल किया कि क्या सरकार फर्जी मुकदमे दर्ज करा रही है। इस पर रेड्डी ने कहा कि जिन 96 मामलों का जिक्र किया गया है, उन सभी मामलों में अदालत का फैसला नहीं आ गया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में आरोपत्र दाखिल किया गया है वहीं कुछ मामलों में अदालत का फैसला नहीं आ गया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में आरोपत्र दाखिल किया गया है वहीं कुछ मामलों में अदालत का फैसला नहीं आ गया है। उन्होंने कहा कि कई मामलों में आरोपत्र दाखिल किया गया है वहीं कुछ मामलों में अदालत का फैसला नहीं आ गया है।

संपादकीय

दिल्ली की कमान

पिछले कुछ वर्षों के दौरान दिल्ली में अलग-अलग मुद्दों पर फैसले लेने के सवाल पर सरकार और उपराज्यपाल के बीच कई मौकों पर स्पष्ट टकराव देखे गए। इसमें एक सवाल मुख्य रहा कि दिल्ली की जनता से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेने और उस पर मंजूरी देने का अंतिम अधिकार आखिर किसके पास है। इस मसले पर सरकार को अक्सर यह शिकायत रही कि दिल्ली के विकास कार्यों को लेकर वह जो भी नीतिगत फैसले लेती है, उस पर बिना किसी मजबूत आधार के उपराज्यपाल की ओर से अड़चन खड़ी की जाती है। जबकि उपराज्यपाल अपने पद से जुड़ी जिम्मेदारी के तहत इस तरह के अधिकारों की लड़ाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और जुलाई, 2018 में शीर्ष अदालत ने स्थिति स्पष्ट कर दी कि दिल्ली के उपराज्यपाल के पास स्वतंत्र फैसले लेने का अधिकार नहीं है और उन्हें मंत्रिपरिषद के सहयोग और सलाह पर कार्य करना चाहिए। इसके अलावा, अदालत ने यह भी कहा कि भूमि, कानून-व्यवस्था और पुलिस को छोड़ कर दिल्ली सरकार के पास अन्य सभी विषयों पर कानून बनाने और उसे लागू करने का अधिकार है। यानी एक तरह से अदालत ने दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की स्पष्ट व्याख्या कर दी। इसके बावजूद बीते कुछ समय से अनेक ऐसे मौके आए जब दिल्ली में विकास कार्यों पर कोई फैसला लेने या उस पर अमल करने को लेकर सरकार और उपराज्यपाल के बीच खींचतान चलती रही। अब सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने लोकसभा में इससे संबंधित जो विधेयक पेश किया है, उसमें उपराज्यपाल को अधिक शक्तियां देने का प्रावधान है। दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2021 के तहत दिल्ली के विधानसभा में पारित कानूनों या मंत्रिपरिषद के फैसलों को लागू करने से पहले उपराज्यपाल को जरूरी मौका देने की बात कही गई है। जाहिर है, अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो दिल्ली सरकार के मंत्रिमंडल को कोई भी कानून लागू करने से पहले उपराज्यपाल की हयारयत्न पर निर्भर होना पड़ेगा। हालांकि पहले भी विधानसभा में कानून पास होने के बाद उपराज्यपाल के पास भेजा जाता था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह महज सूचना देने की औपचारिकता तक सीमित था। लेकिन अब अगर यही पक्ष बाध्यता या नियम के तहत लागू होगी तो स्वाभाविक रूप से यह इस मसले पर दिल्ली सरकार की भूमिका महज औपचारिक रह जाएगी और मुख्य शक्ति उपराज्यपाल के पास केंद्रित रहेगी। यानी व्यवहार में उपराज्यपाल को सरकार के तौर पर देखा गया है। सवाल है कि केंद्र सरकार के इस कदम के बाद दिल्ली में सरकार का जो ढांचा रहेगा, उसमें जनता के प्रति किसकी जवाबदेही रहेगी! क्या यह दिल्ली में चुनी हुई सरकार की भूमिका को कमजोर करने की कोशिश है? अगर दिल्ली में विधानसभा के लिए चुनाव होंगे तो उसमें शामिल पार्टियों के जनता से वोट मांगने का आधार क्या होगा? मौजूदा व्यवस्था में उपराज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं। एक ओर केंद्रीय शक्ति उपराज्यपाल के हाथों में रहेगी, दूसरी ओर दिल्ली और केंद्र में दो विरोधी पार्टियों की सरकार होगी तो ऐसे में मुद्दों पर मतभेद के चलते कामकाज और नीतिगत फैसलों पर अमल को लेकर आखिरी जवाबदेही किसकी और किसके प्रति होगी? जनता के सामने अगर अपने प्रतिनिधियों से जवाब मांगने की नौबत आएगी तो वैसी स्थिति में वह किसी उपलब्धि या कमी के लिए किस जिम्मेदार ठहराएगी? इस विधेयक के पेश होने के साथ ही ऐसे तमाम सवाल उभरना स्वाभाविक है।

है ये किसका शिष्य ?



फिर से पांच पसारता ।

रहना सावधान ॥

है गतिशील वायरस ।

तंग हुआ जहान ॥

नियम पालन हो रहा ।

या हुई ढिलाई ?

लगने को तो लग रही ।

हर पल यहां दवाई ॥

खाकर आया है कसम ।

वायरस अदृश्य ॥

पता नहीं चल पाया ।

है ये किसका शिष्य ?

अक्सर ये आरोप ।

चीन लेकर आया ॥

पर अभी अज्ञात ।

कब हटेगा साया ?

—कृष्णोन्द्र राय

शहरीकरण और रोजगार का संकट

अभिषेक कुमार सिंह

शहरीकरण को विकास का प्रतीक माना जाता है। देश की आबादी का बड़ा हिस्सा शहरों, महानगरों में निवास करता है। यह भी दावा किया जाता है कि आबादी के परिप्रेष्य, अब जितने भी परिवर्तन होने हैं, उनका सीधा असर हमारे शहरों की दशा-दिशा पर पड़ेगा। लेकिन ये शहर कैसे हैं और इनकी भावी रूपरेखा क्या है, इसे लेकर अभी भी कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं बन पाई है। हालांकि इस बीच देश में स्मार्ट शहर जैसी परियोजनाओं का प्रचार जोरशोर से होता रहा है। इस विरोधाभास पर हाल में एक नजर सुगमता के साथ रहन-सहन के उस सूचकांक (ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स) के जरिए डाली गई है, जिसे हाल में केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने जारी किया है। इस सूचकांक से पता चला है कि रहन-सहन के लिहाज से ज्यादातर उत्तर भारतीय शहरों में लापरवाही का आलम पसरा हुआ है, हालांकि दक्षिण भारतीय शहरों ने इस मामले में एक उम्मीद अवश्य जगाई है। रहन-सहन से जुड़े इस सूचकांक में साफ-सफाई और अन्य सहायक विषयों के आधार पर देश के शहरों की श्रेणी निर्धारित की गई है। इसके दो अहम आधार रखे गए। एक वर्गीकरण में उन शहरों को शामिल किया गया, जिनकी आबादी दस लाख से ज्यादा है, जैसे दिल्ली, कानपुर, लुधियाना, बंगलुरु, पुणे और अमदाबाद आदि। जबकि दूसरे में दस लाख से कम आबादी वाले शहरों को रखा गया है। स्वच्छता और सहायकता का पैमाना अपना कर यह तय करने की कोशिश की गई कि रहन-सहन के लिहाज से इन शहरों की गुणवत्ता किस कोटि की है। आकलन में पाया गया कि दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में बंगलुरु, पुणे और अमदाबाद

देश के सबसे अच्छे शहरों में हैं। जबकि दस लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला, भुवनेश्वर और सिलवासा को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान मिला। इसमें एक रोचक आकलन भी सामने आया।

पता चला कि रहन-सहन के स्तर पर बड़े शहरों की सूची में बंगलुरु शीर्ष पर भले ही हो, लेकिन गुणवत्ता के मामले में चेन्नई, कोयंबटूर और नवी मुंबई ज्यादा अच्छे शहर हैं। यहां अहम सवाल यह है कि आखिर शहरों की गुणवत्ता किन पैमानों से आंकी जा सकती है। तो इसका जवाब यह मिला कि सस्ते आवास, साफ पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं की उपलब्धता के अलावा सुरक्षा और मनोरंजन की सुविधाओं तक लोगों की आसान पहुंच से पता चलता है कि कोई शहर रहने लायक है या नहीं। इस तरह के पैमानों पर शहरों के आकलन से कुछ सवालों के जवाब अवश्य मिलते हैं, लेकिन कई अहम और खड़े हो जाते हैं, जिनकी अनदेखी करना मुश्किल है। जैसे यह पूछा जाना चाहिए कि आखिर साफ-सफाई और सहायकता के मामले में हमारे उत्तर भारतीय शहर किस दुविधा में फंसे हुए हैं। शिमला को छोड़ कर कोई अन्य शहर इस लायक क्यों नहीं माना जा रहा है कि वहां एक आम इंसान अच्छा जीवन जी सकता है। यह एक बड़ी विडम्बना है कि हमारी राजनीति में जिस उत्तर भारत का वर्चस्व दिखाई देता है, वह अपने शहरों को दुरुस्त करने के मामले में

दक्षिण भारतीय शहरों से मात खा जाती है। दक्षिण से उत्तर भारत के शहरों के पिछड़ जाने की अहम वजह यह है कि हमारी सरकार भले ही देश के सौ शहरों को स्मार्ट शहरों में तब्दील करने की ख्वाहिशमंद हो, लेकिन उत्तर भारत में अनियोजित ढंग से बसते शहरों की बसावट के उनके अंदाज में घोर बेतरतीबी बिखरी हुई है। इस समस्या



का नतीजा यह निकल रहा है कि सरकारी की योजनाओं के बावजूद खुद-ब-खुद बनने और बिगड़ने वाले ऐसे ज्यादातर शहरों ने शहरीकरण की शकल ही बिगाड़ कर रख दी है। कहा जा रहा है कि 2028 तक हमारा देश दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी-घनत्व वाला मुल्क होगा। यानी अगले छह-सात वर्षों के भीतर इस मामले में हम चीन को पीछे छोड़ देंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि तब वहां जनसंख्या में गिरावट का दौर शुरू हो चुका होगा और भारत की आबादी तेजी से बढ़ रही होगी। यह आकलन संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2013 की जनसंख्या रिपोर्ट का है। आबादी की जरूरतों के मद्देनजर और विकसित देशों की देखादेखी हमारे देश में

शहरीकरण को तो बढ़ावा दिया गया, लेकिन इस तब्दीली का हमारी सरकारों और योजनाकारों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। नतीजा यह निकला कि आज देश के ज्यादातर शहर बेकाबू और अनियोजित फैलाव के शिकार हो गए हैं। इसकी तसदीक वर्ष 2018 में विश्व बैंक की एक अन्य रिपोर्ट छअबनाइजेशन इन साउथ एशिया में की गई थी। इसमें कहा गया था कि भारत में ज्यादातर शहरीकरण बहुत ही गुपचुप ढंग से और बेतरतीबी के साथ हो रहा है। शहरी नियोजन की सारी नीतियों-कवायदों को ताक पर रख कर और आंख मूंद कर होने वाला यह शहरीकरण देश को ऐसी दिशा में ले जा रहा है जिसमें ऐसे शहरों की ऐसी तस्वीर उभरती है जो कूड़े के ढेर से अटे दिखाई देते हैं और जहां की असंख्य इमारतें भूकंप के हल्के से झटके में ढहने को तैयार लगती हैं। शहरों की जिंदगी में सुधार की जरूरत का एक संकेत दो साल पहले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जारी की जाने वाली एनबीएल लिगेबिलिटी इंडेक्स 2019 में भी मिला था। इस सूचकांक में शहरों का आकलन पर्यावरण, संस्कृति, स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा और ढांचागत सुविधाओं आदि पांच प्रमुख मानकों पर किया जाता है। दुनिया के एक सौ चालीस देशों के प्रमुख शहरों में से लोगों के निवास के उपयुक्त शहरों का आकलन करने वाला यह सूचकांक यानी इंडेक्स इकोनॉमिस्ट इंटरलिंग्स यूनिट (ईआइयू) जारी करती है। उल्लेखनीय यह है कि

2019 में इस सूचकांक में भारत के चुनिंदा शहरों की स्थिति और बदतर ठहराया गया था। जैसे देश की राजधानी दिल्ली इस सूचकांक में 2018 के मुकाबले छह स्थान फिसल कर एक सौ अठाहरवें नंबर पर पहुंच गई थी। दिल्ली में वायु प्रदूषण के अलावा अपराधों में बढ़ोतरी को इसकी अहम वजह माना गया था। इसी तरह मुंबई दो पायदान नीचे गिर कर एक सौ उन्नीसवें स्थान पर आ गई थी और इसके लिए वहां नियंत्रण के अलावा सांस्कृतिक गिरावट को जिम्मेदार माना गया था। शहर कैसे भी क्यों न हों- उनकी जरूरत से अब इनकार नहीं किया जा सकता। गांव-कस्बों में रोजगार की कमी और बढ़ती आबादी के बरक्स खेत-खलिहानों का घटता आकार बीते कई दशकों से लोगों को शहरों की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर कर रहा है। अमतौर पर यह पलायन रोकना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अब रोजगार के साथ शहरीकरण देश के विकास की पहली जरूरत है। लेकिन कोरोना वायरस के कारण पैदा हुई स्थितियों में ये समीकरण उलट गए हैं। अब शहरों के लिए जरूरी हो गया है कि वे साफ-सफाई और मूलभूत ढांचे के अलावा स्थायी किस्म के रोजगार सृजन को भी अहमियत दें, ताकि गांव-कस्बों से यहां आने वाली आबादी को कोरोना जैसे संकट के समय सब कुछ छोड़ कर घर वापस लौटने का विकल्प अपनाने को मजबूर न होना पड़े। शहर बनाने और शहर बसाने का मकसद सिर्फ यह नहीं होना चाहिए कि ढांचागत सुविधाओं के आधार पर वह रहने की एक शानदार जगह है, बल्कि यह जरूरी हो गया है कि वहां लोगों को वाजिब कीमत पर आवास के साथ रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन के सारे साधन भी मिलें।

(ममता बनर्जी का दुःख) वो आह भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम

आजकल केंद्र कि सत्ताधारी पार्टी चूँकि वह प्रबल बहुमत में होने से और ऊंगता सूरज होने से उस पार्टी का आकर्षण होना स्वाभाविक हो रहा है। आजकल पार्टी नेता को दूरदृष्टि का रोग होता जा रहा है। नजदीक का कुछ नहीं दिखाई देता है। कारण उनको पूरा भारत वर्ष में उनका या पार्टी को आरोहण करना है। पार्टी का लक्ष्य है पूरा देश को अपनी नियंत्रण में रखना है।

इस शुभ कार्य के लिए साम, दाम, दंड, भेद नीति से पूरा साम्राज्य स्थापित करना ही मुख्य लक्ष्य होता है। जिसके कुछ उदाहरण जैसे मध्य प्रदेश, गोवा आदि में सफल हुए और कई जगह मुंह की खानी पीडी पर चक्रवर्ती बनने का अश्वमेध का घोड़ा अनवरत दौड़ रहा है और हमारे सम्राट बहुत दूर दृष्टि रखते हैं और इतनी अधिक दृढ़निश्चयी हैं जो ठान लिया उसे पूरा किया। रात में नींद में सपना देखा की मोटोरोला मैदान का नाम बदलना है तो आनन फानन

उसका नाम अपने नाम पर रख लिया और क्यों न हों, जब सपना खुद का हो और जब तक सत्ता में हैं तो जनता, धन, मन सब कुछ के मालिक वे ही हैं। चाहे वे चुनकर आये या परम्परागत या अनुवांशिक रूप से आये या बने, बने हैं तो बने हैं, जब तक हैं जान वे ही रहेंगे राजा यदि अकेला होता है तो उसकी प्रवृत्ति होती है अकेलेपन की और दूसरे शब्द में अकडू होता है, कोई अकेले होने से उसमें मिल बैठकर खाने की या कोई वस्तु बांटने नहीं होती, इसका ज्वलंत उदाहरण पी एम् ओ।

ऐसा नहीं की वह उदार नहीं होता, जिन पर प्रसन्न होजाये उन्हें वह फर्श से अर्श तक ले जाता है, अकेला रहने से अनियंत्रित होने से पकवान जैसे अलग अलग स्वाद का खाने की आदत हो जाती है इसलिए अपने साथ अपने देशवासी रसोइया भी रहे हैं जो मनोकुल व्यवस्था करता और जनता भी है, क्योंकि वह वर्षों से साथ में हैं। वह राजा की

भावभंगिमा को जानता और तोलता है।

अब तो पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, मंत्री और यहाँ तक जनता भी बखूबी परिचित हो



चुकी है। अकेले होने के कारण बातों को पचाने की अच्छी पाचन शक्ति है। कोई नहीं जानता कब मन की बात /जनता की आवाज में कौन सी नहीं घोषणा कर दे। ऐसा कहा जाता है की नॉट बंदी की

जानकारी वित्तमंत्री तक को नहीं थी। राफेल की खरीदी के बारे में रक्षा मंत्री को नहीं पता था। गोपनीय बहुत जरूरी है पर कुछ गुप्त काम समय से

उजागर होते हैं। इस समय बंगाल में चुनाव है, वहां पर सत्ता का बिज करने पूरी सरकार के साथ वहां के स्थानीय नेता जी तुंडे से लगे हैं और जीतना भी सुनिश्चित है मजे के बात यह है दोनों

अकेले हैं, यदि दोनों आपस में समझौता करले तो बहुत कुछ समस्या का हल निकल जाएगा। कारण दोनों के एक होने से दोनों के लिए मोदी और दीदी सरकार बन जाएगी बस दोनों को विलय करना है या होगा। देश के मुखिया को ममता के साथ हुई दुर्घटना से सहानुभूति जरूर है, समानुभूति में मात्र कष्ट /दुःख, दर्द का अहसास होता है पर समानुभूति में दर्द दोनों को होता है जैसे लैला को चोट लगती तो मजनु को भी चोट लगती है। हां ममता की पीड़ा का कोई अर्थ नहीं है कारण सरकार उनकी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, पुलिस सब उनकी यहाँ तक की उनको लागी चले नकली कारण उनको चुनाव जीतने के लिए सहानुभूति चाहिए, मुखिया भी सहानुभूति दे रहे हैं, यदि यह सहानुभूति समानुभूति में बदल जाए तो सब किस्म की लड़ाई खतम। जैसा भारत वर्ष में एक उदाहरण है जैन साहित्य में। जब भरत चक्रवर्ती बनने चले तब उनका समाचार

अकेले हैं, यदि दोनों आपस में समझौता करले तो बहुत कुछ समस्या का हल निकल जाएगा। कारण दोनों के एक होने से दोनों के लिए मोदी और दीदी सरकार बन जाएगी बस दोनों को विलय करना है या होगा। देश के मुखिया को ममता के साथ हुई दुर्घटना से सहानुभूति जरूर है, समानुभूति में मात्र कष्ट /दुःख, दर्द का अहसास होता है पर समानुभूति में दर्द दोनों को होता है जैसे लैला को चोट लगती तो मजनु को भी चोट लगती है। हां ममता की पीड़ा का कोई अर्थ नहीं है कारण सरकार उनकी, हॉस्पिटल, डॉक्टर, पुलिस सब उनकी यहाँ तक की उनको लागी चले नकली कारण उनको चुनाव जीतने के लिए सहानुभूति चाहिए, मुखिया भी सहानुभूति दे रहे हैं, यदि यह सहानुभूति समानुभूति में बदल जाए तो सब किस्म की लड़ाई खतम। जैसा भारत वर्ष में एक उदाहरण है जैन साहित्य में। जब भरत चक्रवर्ती बनने चले तब उनका समाचार

उनके भाई बाहुबली के पास पहुंचता है वे स्वयं अधीनता स्वीकार कर ले पर बाहुबली नहीं स्वीकारते हैं, इस पर युद्ध होता है। दोनों तरफ की सेनाएं तैयार होती हैं तब उनके महामंत्रियों ने सलाह दी की यह युध्य आप दोनों का है इसलिए आप दोनों युध्य करे और तीन प्रकार के युध्य निर्धारित किये गए। पहला जल युध्य, दूसरा नेत्र युध्य और तीसरा मल्ल युध्य। तीनों युध्य बाहुबली ने जीते उसी समय उनके मन में भाव आया की मैं इन भौतिक सुख /साधनों के लिए खून के प्यासे हुए। धिक्कार है और वे आत्मकल्याण के लिए राज्य छोड़कर चले गए। बाद में भरत भी चक्रवर्ती बनकर वैराग्य को प्राप्त हुए जिनके नाम से भारतवर्ष नाम रखा गया है। जब टी एम सी के सब नेता बी जे पी में जा रहे हैं तो यदि मुखिया आपस में विलय कर ले तो कोई झंझट नहीं होगी और दोनों का एकधिकार प्रदेश और देश में समान होगा।

भारत में पूंजी की बढ़ती मांग की पूर्ति के लिए करने होंगे नवोन्मेष उपाय

प्रहलाद सबनानी केंद्र सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024-25 तक 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर के आकार का बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को निर्धारित समय सीमा में प्राप्त करने के लिए, भारत में आर्थिक विकास की दर को 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ऊपर ले जाने की आवश्यकता होगी एवं आर्थिक विकास की दर को 10 प्रतिशत से ऊपर ले जाने हेतु देश में पूंजी की अधिक आवश्यकता भी होगी। यदि, वृद्धिशील पूंजी एवं उत्पादन अनुपात 4:1 का भी माना जाये, अर्थात् उत्पादन की एक इकाई हेतु पूंजी की 4 इकाईयों की आवश्यकता होगी, तो 10 प्रतिशत से अधिक की विकास दर हासिल करने के लिए 40 प्रतिशत से अधिक सकल घरेलू बचत की आवश्यकता होगी। हालांकि उत्पादकता में वृद्धि करके वृद्धिशील उत्पादन अनुपात को सुधारा जा सकता है, परंतु यदि रूढ़िवादी दृष्टिकोण को अपनाते हुए भी चलें तो देश की सकल घरेलू बचत में उक्त वृद्धि दर की आवश्यकता तो होगी ही। वर्तमान में देश में बचत दर 30 प्रतिशत से कम है। अतः 10 प्रतिशत से अधिक की विकास दर को प्राप्त करना एवं इसे बनाए रखना एक मुश्किल कार्य होगा और वह भी तब जब देश में विकास दर बढ़ाने हेतु मांग में वृद्धि एवं उपभोग में भी वृद्धि करना आवश्यक होगा। इस स्थिति में

बचत दर में वृद्धि दर्ज करना और भी कठिन कार्य होगा और संभवतः इसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए संसद में घोषणा की थी कि देश में विकास दर को तेज करने के उद्देश्य से केंद्र द्वारा विदेशी मुद्रा में सरकारी बांडज, विदेशी बाजार में जारी कर, विदेशी मुद्रा के रूप में पूंजी जुटाई जाएगी। यदि ऐसा सम्भव हो पाता है तो इससे देश के वित्तीय बाजार पर पूंजी उगाहने के दबाव को कम किया जा सकता है अन्वथा यह राशि केंद्र सरकार को देशी वित्तीय बाजार से उगाहनी होती है। साथ ही यदि केंद्र सरकार यह राशि देशी वित्तीय बाजार से न उगाह कर विदेशी वित्तीय बाजार से विदेशी मुद्रा में उगाहती है तो देशी वित्तीय बाजार द्वारा वह बची हुई राशि देश के उद्योगों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जा सकती है।

केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में की गई उक्त घोषणा के साथ ही, देश में एक बहस-सी छिड़ गई थी कि देश द्वारा विदेशी बाजार से विदेशी मुद्रा में पूंजी उगाहने से विश्व की गलत संदेश जाएगा क्योंकि विदेशों से विदेशी मुद्रा की उगाही कुछ असामान्य परिस्थितियों में ही की जानी चाहिए, जबकि अभी देश की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होने के बावजूद विदेशों से पूंजी की उगाही क्यों की जाये? परंतु, यहां यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि विदेशों से विदेशी मुद्रा में पूंजी

की उगाही देश की आर्थिक वृद्धि दर तेज करने के उद्देश्य से की जा रही है। ऐसा कई अन्य देशों द्वारा भी समय-समय पर किया जाता रहा है। भारत ने जरूर इस पथ का इस्तेमाल नहीं के बराबर किया है। इसी कारण से भारत का विदेशी मुद्रा में सम्प्रभु ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात अन्य देशों की तुलना में



बहुत ही कम (लगभग मात्र 5 प्रतिशत) है। जबकि, अन्य देशों यथा चीन, जापान एवं अमेरिका के लिए यह प्रतिशत बहुत ही अधिक है। भारत का कुल विदेशी ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद का मात्र लगभग 20 प्रतिशत ही है तथा भारत का कुल ऋण देश के सकल घरेलू उत्पाद का 72.3 प्रतिशत (वर्ष 2019 में) है। देश का विदेशी व्यापार घाटा भी सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 2.7

प्रतिशत ही है। तथा देश के पास 48,000 करोड़ अमेरिकी डॉलर से अधिक का विदेशी भंडार भी मौजूद है। उक्त समस्त मानकों पर भारत की स्थिति बहुत ही संतोषजनक कही जा सकती है।

कई अर्थशास्त्रियों द्वारा यह तर्क भी दिया जा रहा है कि चूंकि यह ऋण विदेशी मुद्रा में लिया जाएगा

अतः इसका भुगतान भी विदेशी मुद्रा में ही करना होगा और आज से लेकर दीर्घकालीन अवधि (15 या 20 वर्षों) के पश्चात रूपए का बाजार मूल्य क्या होगा यह अभी भी बताना बहुत मुश्किल कार्य है। अतः हम अपनी देवता का पता आज से 15-20 वर्षों पश्चात कैसे लगा पाएंगे? विदेशी बाजारों में ब्याज की दर (2-3 प्रतिशत के आसपास) हमारे देश में प्रचलित ब्याज दर (7-8 प्रतिशत के

आसपास) की तुलना में बहुत कम है। अतः भारत सरकार द्वारा विदेशी मुद्रा में जारी किए जाने वाले बांडज की ब्याज दर भी बहुत कम अर्थात् 2-3 प्रतिशत के आसपास ही होगी। भारतीय रूपए एवं अमेरिकी डॉलर (यदि बांडज अमेरिकी डॉलर में जारी किए जाते हैं तो) की दर हेजिंग/स्वॉप के माध्यम से अभी से ही निश्चित की जा सकती है। हां, यहां हेजिंग/स्वॉप लागत (विनिमय लागत) जरूर इस 2-3 प्रतिशत ब्याज दर में जोड़नी होगी, जोकि लगभग 3 से 3.5 प्रतिशत के बीच हो सकती है। इसी तरह अन्य लागतों को जोड़कर इन बांडज की कुल लागत 6-7 प्रतिशत के बीच में रह सकती है। इस प्रकार, लागत तो भारत में लागू प्रचलित की दर तुलना में थोड़ी ही कम होगी परंतु देश में अमेरिका डॉलर की आवश्यकता बढ़ने से भारतीय रूपए को मजबूती प्रदान हो सकती है एवं देश में 15-20 वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा में पूंजी उपलब्ध हो जाएगी जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए अपना योगदान देती रहेगी। साथ ही, विदेशी बाजार में सस्ती ब्याज दरों पर यदि वे बांडज जारी होंगे तो देश में भी सरकार द्वारा जारी किए जा रहे अन्य बांडज पर आय (यौलड) में कमी आ सकती है जिससे देश में ब्याज दरों में कमी आ सकती है तथा वित्त बाजार में तरलता की स्थिति में और अधिक सुधार आएगा। यदि हमारे देश में आर्थिक विकास की गति को तेज करना है

एवं देश में पर्याप्त पूंजी उपलब्ध नहीं हो तो विदेशी मुद्रा में पूंजी का उपयोग करने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अभी तो भारत की रेटिंग भी विदेशी बाजारों में काफी अच्छी है। अतः विदेशी मुद्रा में पूंजी आसान शर्तों पर एवं तुलनात्मक रूप से कम ब्याज की दर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। जापान में तो ब्याज की दर भी बहुत कम अर्थात् 0.10 प्रतिशत ही है। यदि जापानी येन में भारत सरकार इन बांडज को जारी करती है तो ब्याज की दर बहुत ही कम रहने की सम्भावना होगी। अतः भारत सरकार को विदेशी बाजारों में विदेशी मुद्रा में बांडज को जारी करना चाहिए। हां, शुरू में इसका देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव आंकने के उद्देश्य से, छोटे-छोटे हिस्सों यथा 300-400 करोड़ अमेरिकी डॉलर में या सरकारी बांडज जारी किए जा सकते हैं तथा विदेशी मुद्रा में जारी किए जा रहे बांडज हेतु देश में ही इनके व्यापार करने के उद्देश्य से बाजार उपलब्ध कराने हेतु ये बांडज विभिन्न समय सीमा के लिए यथा 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष आदि हेतु जारी किए जा सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार बहुत बड़ा है और यदि केवल 1000 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक के बांडज विदेशी बाजारों में जारी किया जाते हैं तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर कोई विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना लगभग शून्य ही होनी चाहिए।

प्रेरणा ज्ञानोत्सव में शिक्षकों ने लिया प्रेरक ब्लॉक बनाने का संकल्प

प्रखर पिंडरा वाराणसी। परिषदीय विद्यालयों में चलाए जा रहे 100 दिवसीय कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह बुधवार को बाबतपुर स्थित बीआईटी कालेज परिसर में मनाया गया। जिसमें

अभिभावकों को जागरूक होने की जरूरत : पवन सिंह

शिक्षकों, पुरातन छात्रों व अध्वनरत छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पिंडरा विधायक डॉ. अवधेश सिंह के प्रतिनिधि पवन सिंह रहे। उन्होंने कहा कि आज पिंडरा ब्लॉक का हर स्कूल अपनी कायाकल्प व शिक्षकों के प्रयास से पहचान बना चुका है। बस प्रेरक ब्लॉक बनने व गुणवत्ता में सुधार के लिए अभिभावकों को जागरूक होने की जरूरत है। विशिष्ट अतिथि डायट प्रचार्य उमेश शुक्ला ने कहा कि शिक्षा के मूल



आधार शिक्षक और शिक्षार्थी है। उनके प्रयास से गुणवत्ता प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने प्रेरक ब्लॉक बनाने के लिए शिक्षकों और अभिभावकों को आगे आना होगा। इसके पूर्व माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यापण व दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथिद्वय द्वारा किया गया। इस दौरान प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा उत्सव, शिक्षा चौपाल,

दीक्षा व रीड एलांग एप समेत अनेक बिंदुओं पर वक्ताओं ने प्रकाश डाला। खण्ड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह ने अतिथियों व कायाकल्प में सहयोग देने वाले पुरातन छात्रों का स्वागत किया। संचालन रामसेवक यादव व धन्यवाद ज्ञापन डॉ. कुंवर पंकज सिंह ने किया। इस दौरान पुरातन छात्र व वर्तमान में एमएचआई के

डायरेक्टर अवधेश सिंह, पूर्व डिप्टी एसपी मृत्युंजय सिंह, पूर्व प्रवक्ता दयाशंकर सिंह, लल्लन सिंह, डॉ. गौरव पांडेय, शरद सिंह अंशु, जिला पंचायत सदस्य गौतम सिंह, ग्राम प्रधान विनय सिंह व राजेन्द्र पटेल समेत दो दर्जन पुरातन छात्रों व 40 शिक्षकों तथा एक दर्जन अध्वनरत छात्रों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। समारोह के दौरान पीपीटी के माध्यम से प्रेरणा ज्ञानोत्सव के बाबत विस्तृत रूप से उपस्थित शिक्षकों को दो गई। अंत में पिंडरा ब्लॉक के सैकड़ों शिक्षकों के द्वारा ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनाने के संकल्प के साथ समापन हुआ।

बच्चों के विद्यालय स्थानान्तरण रोकने को लेकर डीएम से मिले सपा महानगर अध्यक्ष



प्रखर पूर्वांचल वाराणसी। कर्मोचित विद्यालय को स्थानान्तरण रोकने को लेकर तथा पूर्ववत संचालित करने के लेकर समाजवादी पार्टी के सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने आज जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से रायफल क्लब में मुलाकात कर पत्रक सौंपा श्री शर्मा ने जिलाधिकारी से कहा कि औसासनंज -2 दारानगर में स्थित कर्मोचित विद्यालय स्टेट फोल्ड रोड पीलीकोटी में स्थानान्तरित करने से छोटे छोटे बच्चे दुर्घटना का शिकार होंगे। क्षेत्रीय पार्षद मनोज यादव ने कई बार शिक्षा विभाग के अधिकारियों को लिखित व मौखिक शिकायत दर्ज कराया मगर अधिकारी कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं जिससे छोटे छोटे गरीब घरों के

बच्चों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। सपा महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा ने बताया कि प्राइमरी विद्यालय औसासनंज - 2 दारानगर में लगभग साठ वर्षों से उपर विद्यालय में शिक्षा संचालित होता आया व वर्तमान में 85 बच्चे पठन पाठन करते हैं विद्यालय को पीलीकोटी में स्थानान्तरण करने से गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित होंगे। जिलाधिकारी से मिलने वाले मे प्रमुख रूप से महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी विष्णु शर्मा, महासचिव जितेंद्र यादव, युवजन सभा जिलाध्यक्ष किशन दीक्षित, पार्षद मनोज यादव, दिलशाद अहमद (दिल्लू), विवेक सिंह, दीपक सिंह, जावेद अंसारी, सुरेश यादव, अजय मिश्रा आदि रहे।

2 किलो 900 ग्राम अवैध गांजा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

प्रखर ब्यूरो गाजीपुर। पुलिस अधीक्षक के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत अपर पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सैदपुर के निकट पर्यवेक्षण मे 17 मार्च 2021 को उ0नि0 जयप्रकाश सिंह मय हमराह फौर्स के थाना क्षेत्र में मामूर थे कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति कटया चढ़ी पर खड़ा होकर सैदपुर जाने वाली बस का इंतजार कर रहा है, जिसे हाथ में लिये हुआ है। मुखबिर की सूचना पर विश्वास कर पुलिस वालों के पास चढ़ी के पास पहुँचे तो देखे कि एक व्यक्ति जो अपने हाथ में झोला लिये था, पुलिस वालों को देखकर अचानक पीछे मुड़कर भागने लगा कि उसे करीब 25-30



कदम रोड पर ही दौड़ाकर घेरकर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति का नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम चन्द्रजय उर्फ बिहारी पुत्र राममूरत ग्राम देईपुर, थाना बहरियाबाद, जनपद गाजीपुर बताया तथा भागने का कारण पूछा गया तो उसने बताया कि मेरे पास

गांजा है जिसे बेचने के लिए मैं ले जा रहा था कि आप लोगो द्वारा पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्ति की तलाशी ली गयी तो दाहिने हाथ में लिए प्लास्टिक के झोले में अखबारी कागज में लपेटकर रखा हुआ कुल 2.900 किग्रा. अवैध गांजा मिला।

प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह बीआरसी पर संपन्न

प्रखर सेमरियावां। संत कबीरनगर। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा सत्येंद्र कुमार सिंह के निर्देशानुसार बुधवार को सभी ब्लॉकों में प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम आयोजन किया गया। बीआरसी सेमरियावा पर आयोजित कार्यक्रम में ब्लॉक के सभी परिषदीय विद्यालय के शिक्षक, अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष समारोह में शरीक हुए। इस अवसर पर मुख्य अतिथि खंड विकास अधिकारी, विजय कुमार पांडेय ने कहा की प्रदेश सरकार बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु संकल्पित है। कायाकल्प योजना के तहत सभी परिषदीय विद्यालय माडल स्कूल बनने छात्र छात्राओं को सभी संसाधनों सहित सुसज्जित स्कूल में गुणवत्ता युक्त शिक्षा का प्रबंध किया गया है। मिशन प्रेरणा प्राथमिक शिक्षा को मजबूत

करेगी। उन्होंने उपस्थित शिक्षकों को आश्चर्य किया की सेमरियावां ब्लॉक को प्रेरक ब्लॉक बनने हेतु हर प्रकार की मदद की जाएगी। मुख्य अतिथि ने ब्लॉक के प्रेरक बालक, बालिकाओं और शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन संजय दिवेदी, राजीव उपाध्याय, विनोद कुमार ने सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने, कोविड प्रोटोकाल के प्रति जागरूकता, विद्यालय प्रबंध समिति की सहभागिता, संचित बस्ती में शिक्षा की चौपाल, नए सत्र में स्कूल चलो अभियान पर था स्कूलों में बच्चों नामांकन पर चर्चा की गई। खंड शिक्षा अधिकारी बी पी मिश्र ने शिक्षकों को प्रेरित व उत्साहित करते हुए कहा की अभिभावकों के साथ मिशन प्रेरणा के लक्ष्य को साझा

करें। अभिभावकों को शिक्षा के प्रति सचेत व सजग करें मिशन प्रेरणा व कायाकल्प से आमजन जोड़ें। इस कार्यक्रम में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक तथा कंपो जित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/ ई प्र०, एसएमसी अध्यक्ष व जागरूक अभिभावकों मौजूद रहे। बड़ी संख्या में महिला अभिभावक भी शामिल हुईं। प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह के अवसर पर विकास खंड सेमरियावा में शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट व सराहनीय कार्य हेतु जफेर अली फरखी, विनोद कुमार यादव, कूल चंद्र, जलालुद्दीन, अश्विनी कुमार चौधरी, पशुपति नारायण, अब्दुलहीम, शमीम मन्सूर, मनोज कुमार अहिल, मुस्ताक अहमद, शकील अहमद एवं चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, असरारुल हक को प्रमाणपत्र देकर सम्मानित व उत्साहवर्धन किया।

शैक्षिक गुणवत्ता के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का हुआ शुभारंभ

प्रखर पिंडरा वाराणसी। पिंडरा विकास खण्ड के बीआरसी मंगारी पर बुधवार से शिक्षकों के अध्यापन कार्य में गुणवत्ता लाने के उद्देश्य से दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ खण्ड शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार सिंह के द्वारा किया गया। उक्त प्रशिक्षण में शिक्षकों को आधारशिला क्रिया-न्यून, संदर्शिका, समृद्ध हस्तपुस्तिका, फ्रिंट रिच मैटेरियल्स व गणित किट के सार्थक प्रयोग के बाबत प्रशिक्षण शुरू किया गया। बीडओ अशोक कुमार सिंह ने बताया कि दो दिन तक चलने वाले

प्रशिक्षण के दौरान शिक्षकों के कोविड 19 के बाद खुले स्कूलों में शिक्षण कार्य करने के नए विधाओं से परिचित कराने के साथ उपचारात्मक शिक्षक पर बल दिया जाएगा। 5 फेरे के माध्यम से प्राथमिक विद्यालय के सभी शिक्षकों व शिक्षामित्रों को यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले फेरे में 5 बैच बनाकर 200 शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सन्दर्भदाता गौतम दत्ता, संजय वर्मा, कमलेश कुमार व पप्पू गिरी समेत 10 सन्दर्भदाता द्वारा शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया गया।

प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का आयोजन

प्रखर सुस्थाकला जौनपुर। क्षेत्र के अभिनव पूर्व माध्यमिक विद्यालय अशोकपुर कला मे बुधवार को खण्ड शिक्षा अधिकारी आर एन पाठक के नेतृत्व में प्रेरणा ज्ञानोत्सव समारोह का आयोजन किया गया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र प्रमुख कविता वर्मा व विशिष्ट अतिथि द्वय हृदय प्रसाद सिंह रानु व पूर्व प्रधानाचार्य डाक्टर रणजीत सिंह ने मा. शारदा के चित्र पर माल्यापण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत किया गया तत्पश्चात शिक्षा क्षेत्र के संकुल स्तर के बच्चों के द्वारा जहाँ एकल गीत, कौव्याली, भाषण कला आदि में एक से बढ़कर एक शिक्षा प्रद कार्यक्रम प्रस्तुत किया वहीं संकुल स्तर पर टीएनएम के माध्यम से शैक्षिक स्टाल लगाकर उपस्थित लोगों को परिषदीय शिक्षा के प्रति प्रेरित करने का प्रयास किया गया कार्यक्रम में परिषदीय शिक्षा में बेहतरीन कार्य करने वाले 12 अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों तथा भाषा और गणित पर नियन्त्रण रखने वाले 9 बच्चों को मुख्य अतिथि द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।

तीसरे दिन भी आमरण अनशन रहा जारी, एक छात्र की हालत खराब व एक छात्र नेता ने जल का भी किया त्याग

प्रखर ब्यूरो गाजीपुर। स्नातकोत्तर महाविद्यालय गाजीपुर में छात्रसंघ चुनाव कराने को लेकर तीसरे दिन भी आमरण अनशन जारी रहा। तीसरे दिन अनशनरत छात्रों कि तबियत बिगड़ने पर अनशनरत प्रवीण पाण्डेय को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बात पर चिंता और शोक प्रकट करते हुए पूर्व छात्रसंघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने कहा कि गाजीपुर की धरती क्रांतिकारियों की धरती रही है और यहाँ के जवानों ने अपने हक और अधिकार के लिए कभी अपने जीवन और मौत का भी कभी फिक्र नहीं किया। इन्ही को अपना आदर्श मानते हुए अनशनरत प्रवीण पाण्डेय की हालत खराब होने के बावजूद हमारा अनशन पूर्व मांग पूर्ण होने तक जारी रहेगा। कालेज प्रशासन का अड़िबल रवैया ब्रिटानिया हुकुमत के दमनकारी नीति जैसा है। बेहतर नीति प्रशासन जिस तरह से हम छात्रों के प्रति अपनी संवेदनहीनता का परिचय दे रहा है उसे गाजीपुर का छात्र कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा और हम छात्र नेता छात्र संघ चुनाव करायें जाने के अपने उचित मांग के समर्थन में



अपने अनशन को और भी उग्र व भीषण करते चले जाएँ भले ही हमें अपने प्राणों का उर्समर् हो ब्यू न करना पड़े। इसक्रम में अनशनरत छात्र नेता दीपक उपाध्याय ने अन्न के साथ ही साथ आज से जल का भी त्याग कर दिया है और जल का यह त्याग मांग पूर्ण होने तक जारी रहेगा। सदर अस्पताल कि डाक्टर टीम द्वारा सभी अनशनरत छात्रों का मेडिकल परीक्षण किया गया, आमरण अनशन का नेतृत्व कर रहे दीपक उपाध्याय ने बताया कि आंदोलन को दो टीम बनाकर आमरण

अनशन जारी रखा जाएगा, एक टीम सदर अस्पताल गौराबाजार में आमरण अनशन जारी रखेगा और दूसरी टीम पीजी कॉलेज में जारी रखेगा। इस दौरान छात्र नेता शुभम कुशवाहा ने कहा कि जब तक छात्र संघ चुनाव कि तिथि घोषित नहीं की जाती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। अनशन कर रहे दीपक कुमार, कमलेश यादव, धर्मेंद्र विश्वकर्मा, दीपक भाई, किशन यादव, पीयूष बिंद, जगनारायण भारती, अक्षय यादव, प्रवीण पाण्डेय, दीपक उपाध्याय, अजय कुमार भारतीय, अनिल कुमार, संदीप यादव, प्रदीप यादव, शुभम कुशवाहा के समर्थन में आज धरना शामिल होने वाले छात्र में मुख्य रूप जिला अध्यक्ष क्षत्रिय महासभा राजकुमार सिंह, छात्र नेता सिध्दार्थ सिंह, शशांक उपाध्याय, शमीरी सिंह, मनीष चौधरी, पूर्व छात्र अध्यक्ष सम्पूर्णानंद यादव, पूर्व महामंत्री सुधांशु तिवारी, नितिन कुमार सिंह, बृजेश सिंह, रूद्र प्रताप चौबे, राजू कुमार कनौजिया, जितेंद्र विश्वकर्मा, कृष्णा यादव, अभिषेक कौसिया, सौरभ सिंह यादव, दीपक कुशवाहा, अजय थे।

हाईटेक हो रहे हैं यूपी के परिषदीय विद्यालय : गिरिश चंद्र यादव

खंड शिक्षा अधिकारी राजीव यादव ने राज्यमंत्री को भेंट किया स्मृति चिन्ह, शाहगंज ब्लॉक को जिले का प्रथम प्रेरक ब्लॉक बनाने का बीईओ ने किया दावा

प्रखर खेतासराय (जौनपुर)। प्रदेश के आवास एवं शहरी नियोजन राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश के परिषदीय विद्यालय पूरी तरह से हाईटेक हो रहे हैं। यहाँ के प्रतिभाशाली बच्चे व उन्हें शिक्षित करने वाले शिक्षक, शिक्षिकाएँ बहने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने के लिए प्रेरणा ज्ञान उत्सव समारोह में खूब छटा बिखेर रहे हैं। लव बुधवार को नगर पंचायत खेतासराय कस्बा में स्थित केंद्रीय प्राथमिक विद्यालय में आयोजित प्रेरणा ज्ञान उत्सव समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। उन्होंने समारोह में विभिन्न विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा लगाए गए स्टाल का सूक्ष्म निरीक्षण किया। इस दौरान बच्चों द्वारा सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने, पानी बचाने, बाल विवाह रोकने, शिक्षा को तस्करी का मुकाम बनाने जैसे तमाम मॉडल के रूप में विकसित करके लोगों को दिखाया। समारोह



का उद्घाटन राज्यमंत्री श्री यादव ने फीता काटकर और दीप प्रज्वलन से किया। उन्होंने शाहगंज विकासखंड के खंड शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव की लगनशीलता की खुलकर सराहना की, कहा पिछले कई वर्षों से राजीव कुमार ने शाहगंज ब्लॉक के विद्यालयों को जिस प्रकार हाईटेक करने का सफल प्रयास किया वह प्रशंसनीय है। खण्ड शिक्षा अधिकारी राजीव कुमार यादव ने सभी शिक्षकों को प्रेरित करते हुए

बताया कि विकास खण्ड शाहगंज जनपद का सबसे दूरस्थ व बड़ा ब्लॉक होने के बावजूद यहाँ पर मिशन प्रेरणा एवं कायाकल्प योजना के अंतर्गत सर्वाधिक कार्य हुआ है। यहाँ के शिक्षकों ने सबसे अधिक नामांकन करते हुए रिकॉर्ड बनाया है, विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में यहाँ के परिषदीय स्कूलों के छात्रों ने सफलता प्राप्त करने के साथ ही उच्च मुकाम हासिल किया है। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका शाहगंज

बच्चों के मॉडल देख प्रसन्न हुए मंत्री

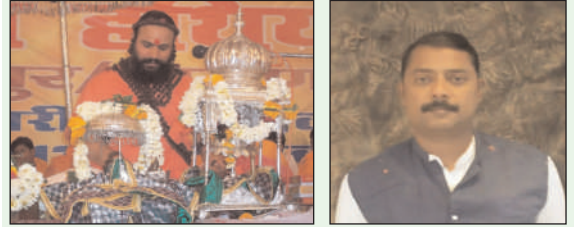
प्रखर खेतासराय जौनपुर। शाहगंज सौंधी ब्लॉक के चार न्याय पंचायत खेतासराय, पारा कमाल, जमदहौं और रुधौली के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों में कन्या प्राथमिक विद्यालय बिसवाँ, प्राथमिक विद्यालय रुधौली, कर्मोचित विद्यालय अर्जुनपुर, प्राथमिक विद्यालय गौरी, युनुपुर, मनेछ विद्यालय शेखपुर मनसूर अली, प्राथमिक विद्यालय शाहपुर, गोधना, खेतासराय समेत तमाम विद्यालय के अध्यापक ने स्टाल लगाया। शाहगंज ब्लॉक के बीडीओ राजीव यादव, खंड विकास अधिकारी अनुराग राय ने राज्यमंत्री श्री यादव को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर इओ अमित कुमार, अशोक मौर्य, अखिलेश यादव अमित मौर्य अन्य मौजूद रहे।

वर्दान से अभिनव जूनियर हाईस्कूल गुरैनी की छात्राओं द्वारा किया गया जिनकी जोरदार प्रस्तुति ने सभी को तालियां बजाने हेतु मजबूर कर दिया। कार्यक्रम का संचालन प्रधानाध्यापक डॉ० सभाजीत यादव एवं अध्यक्षता खण्ड विकास अधिकारी अनुराग राय ने किया। इस अवसर पर बदीउज्जमा, वीरेंद्र कुमार, अखिलेश कुमार यादव, दिनेश कुमार यादव, सुबास यादव, प्रशान्त मिश्र, धर्मेंद्र सिंह, मोहम्मद नूरुसफा, वीरेंद्र सिंह, डॉ अभिषेक सिंह, कृष्ण मुरारी मौर्य, अशोक कुमार सोनकर, राम सकल यादव, राजेशशा सिंह, मनोज कुमार यादव, राधेश्याम मिश्र, डॉ० सुरेश चंद्र मौर्य, अनिरुद्ध मौर्य, पंकज कुमार सिंह, अशोक मौर्य, सुधा गौतम, अनिता पाठ, रेनु आर्या, खुशींद आलम, चंद्रमणि मिश्र, डॉ० शिवानी मौर्य, सबा परवीन, जनाला अंजुम, ममता गुप्ता, डॉ अमलेंद्र गुप्ता अन्य सम्मिलित रहे।

प्रयोग एवं नवाचारों के द्वारा प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों, शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों तथा कायाकल्प योजना में विद्यालयों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रधानों के साथ साथ ग्राम पंचायत अधिकारियों को मिलाकर कुल 150 लोगों को सम्मानित करते हुए उनके कार्यों की सराहना की गयी। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश

संक्षिप्त खबरें

राजनीति नहीं, वैदिक सनातन धर्म का पालन करता है सिद्धपीठ-श्रीराम जायसवाल



प्रखर दुल्लहपुर (गाजीपुर)। सिद्धपीठ हथियाराम मठ के पीठाधीश्वर रहते हुए अनवरत धार्मिक अनुष्ठान व सिद्धपीठ की कठिन आचार संहिता का पालन करते हुए सामाजिक कार्यों में एक स्तंभ के रूप में स्थापित हो चुके महामंडलेश्वर स्वामी भवानीनंदन यति जी महाराज पर 2014 लोकसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से गाजीपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए काफी दबाव बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व चाहता था कि श्री यति जी गाजीपुर लोकसभा से चुनाव लड़ें। ऐसे में इस कार्य के लिए उन्हें राजी करने के निमित्त राजनैतिक सामाजिक क्षेत्र के दिग्गजों के साथ ही भाजपा के अनुष्ठीक संगठनों से जुड़े संत महात्माओं द्वारा भी काफी प्रयास किए गए। लेकिन बड़ी अडिगता के साथ श्री भवानीनंदन यति जी महाराज ने कहा कि राजनीति हमारा धर्म नहीं है। सिद्धपीठ हमें वैदिक सनातन धर्म के पालन का संदेश देता है जिसका निर्वहन करना ही हमारा दायित्व है। उन्होंने सिद्धपीठ की परंपरा का निर्वहन करते हुए पिछले 25 पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन गुरुजनों की तपस्या व साधना को ध्यान में रखते हुए राजनीति में जाने के दबाव आग्रह को विनम्रता पूर्वक नजरअंदाज कर गए। हालांकि उनके इस निर्णय से भाजपा के कुछ दिग्गज उनसे असंतुष्ट हुए लेकिन उन्होंने सिद्धपीठ की महत्ता को बरकरार रखते हुए चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया।

देश के प्रधानमंत्री के पुरोहित गंगाधर पाठक के द्वारा ब्रज एवं पर्यावरण को किया सम्मानित



प्रखर मथुरा। श्री संकट मोचन योग अनुसंधान केंद्र कुंभ वृन्दावन में बैठक वेदांग महोत्सव में ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जनजागरूकता समिति रजि उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय योग गुरु बालमुकुंद शास्त्री योगाचार्य के द्वारा समाज के लिए उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए टीम किया सम्मानित ' अतिथि के रूप में शामिल हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुरोहित पंडित गंगाधर शास्त्री के द्वारा पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया ' कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में पूरे भारतवर्ष आये विद्वान सभी ने अपने अपने विचार प्रकट किए ' सम्मान पाने वालों में प्रदेश महासचिव सत्यदेव शर्मा, प्रदेश संगठन मंत्री मुकेश शर्मा, प्रदेश सचिव प्रदीप शर्मा, महानगर अध्यक्ष अर्जुन पंडित उर्फ निकुंज , युवा जिलाध्यक्ष हरबीर चौधरी, युवा महानगर अध्यक्ष विनोद पांडे, महिला प्रकोष्ठ महानगर अध्यक्ष सुनीता उपाध्याय श्रीमती जमुना शर्मा, चंद्रकांत पांडे, कुलदीप शास्त्री, हेमंत वर्मा, कुलदीप शास्त्री प्रवीण मिश्रा शामिल रहे ' इस अवसर प्रदेश अध्यक्ष विनोद दीक्षित, महिला प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती श्वेता शर्मा ने सभी को दी बधाई।

मेडिकल कैम्प लगाकर पुलिस कर्मियों व उनके परिजनों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण



प्रखर संतकबीरनगर। रिजर्व पुलिस लाइन संतकबीरनगर मे पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर डॉ कौस्तुभ द्वारा पुलिस कर्मियों व उनके परिजनों के स्वास्थ्य हित को देखते हुये दिने गये निर्देश का अनुपालन मे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया । जिसमे जिला चिकित्सालय संतकबीरनगर के चिकित्सकों द्वारा पुलिस कर्मियों व उनके परिजनों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुये उचित परामर्श दिया गया एवं औषधि का वितरण किया गया । पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा स्वयं मेडिकल कैम्प में जाकर पुलिसकर्मियों के स्वास्थ्य परीक्षण का जायजा लिया गया व पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य के संबंध में उचित दिशा-निर्देश दिया गया ।

एन्टीरोमियो वैकिंग के दौरान 07 शोहदों से माफिनामा भरवाकर सख्त हिदायत देते हुए छोड़ा गया



प्रखर संतकबीरनगर। पुलिस अधीक्षक डा0 कौस्तुभ के मार्गदर्शन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं पर होने वाले अपराधों के रोक थाम हेतु प्रभारी एण्टी रोमियो उ0नि0 श्रीमती गौरी शुक्ला द्वारा विभिन्न स्थानों पर बालिकाओं / महिलाओं से उनकी सुरक्षा के संबंध में वार्ता की गई व उ0प्र0 पुलिस द्वारा चलायी जा रही सुरक्षा संबन्धित एम / 112 / युमैन पावर हेल्प लाइन 1090 / यूपी कॉर्पो / 181, पुलिस कंट्रोल नंबर 112 चाइल्ड हेल्प लाइन-1098 के बारे में के बारे में जागरूक किया गया व इन नंबरों के प्रयोग हेतु छात्राओं को प्रोत्साहित किया गया तथा पंपलेट का भी वितरण किया गया, इसके अतिरिक्त विभिन्न स्थानों पर एण्टी रोमियो प्रभारी द्वारा बेवजह घूम रहे 07 शोहदों से माफिनामा भरवाकर सख्त हिदायत देते हुए छोड़ा गया ।

